**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 981**

**05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**चुरू में चिकित्सा कर्मचारियों की कमी**

**981. श्री राहुल कस्वां:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान राज्य के चुरू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में चिकित्सकों, विशेषज्ञों, नर्सिंग स्टाफ और प्रयोगशाला तकनीशियनों की वर्तमान उपलब्धता कितनी है और रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए भवन निर्माण, उपकरण खरीद, प्रयोगशाला उन्नयन या एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त संसदीय क्षेत्र में टेलीमेडिसिन, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां या डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए प्रोत्साहन-आधारित नियुक्तियां, संविदा नियुक्तियां या विशेष भर्ती अभियान चलाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या देश में रोगियों की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन सेवाओं, मातृ स्वास्थ्य और बाल चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (ङ): राजस्थान सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान के चुरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में स्वीकृत और रिक्त चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञों, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम और लैब तकनीशियनों के कुल पदों का विवरण निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | पदनाम | स्वीकृत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|
| 1. | चिकित्सा अधिकारी | 229 | 37 |
| 2. | विशेषज्ञ | 101 | 54 |
| 3. | नर्सिंग स्टाफ | 517 | 101 |
| 4. | एएनएम | 244 | 18 |
| 5. | लैब तकनीशियन | 184 | 59 |

उपरोक्त के अतिरिक्त, चुरू लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में 615 संविदा कर्मचारी भी तैनात हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और सीमांतक समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पहुँच में सुधार हेतु सहायता करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार प्रस्तावों को मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में स्वीकृति प्रदान करती है।

चूरू लोकसभा क्षेत्र में 214 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित 1.80 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से, उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके, प्रसूति एवं शिशु देखभाल केंद्रों और बुनियादी आपातकालीन देखभाल सहित 12 विस्तारित सेवाओं के पैकेज के साथ व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। विस्तारित सेवाओं के पूरक के रूप में, दवाओं और निदान की आवश्यक सूची का विस्तार किया गया है ताकि सीएचसी में 300 दवाएं और 97 निदान, पीएचसी में 172 दवाएं और 63 निदान और एसएचसी में 106 दवाएं और 14 निदान उपलब्ध कराए जा सकें।

64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का उद्देश्य उप-स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों, एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और गहन चिकित्सा अस्पताल ब्लॉकों के लिए अवसंरचना विकास हेतु सहायता प्रदान करना है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से पाँच वर्षों (2021-2026) की अवधि में कुल 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।

राजस्थान सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चुरू लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 24 एम्बुलेंस (108 के अंतर्गत 18 और जननी एक्सप्रेस के अंतर्गत 6) उपलब्ध हैं, जिनमें पहले से अनुपयोगी हो चुके वाहनों के बदले में लाए गएवाहन भी शामिल  किए गए हैं। एनएचएम के अंतर्गत, मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) देश भर में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिनमें चुरू लोकसभा क्षेत्र में 4 एमएमयू शामिल हैं।

देश भर में कार्यरत एएएम पर उपलब्ध टेली-परामर्श सेवाएँ लोगों को उनके घरों के पास ही विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाती हैं, जिससे व्यक्तिगत पहुँच, देखभाल की लागत में बचत, सेवा प्रदाताओं की कमी जैसी समस्याओं का समाधान हो जाता है और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित होती है। राजस्थान सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अप्रैल, 2025 से अक्टूबर, 2025 के बीच, चुरू लोकसभा क्षेत्र में ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुल 7,916 टेली-परामर्श प्रदान किए गए हैं।

भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए चिकित्सा व्यवसायियों को प्रोत्साहन और मानदेय के रूप में कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकोंए को दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाता है, ताकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवा करना आकर्षक लगे।

ii. विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए राज्यों को बातचीत करके तय किए गए वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "आप बोली लगाएँ, हम भुगतान करें" जैसी रणनीतियों में लचीलापन भी शामिल है।

iii. एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वरीयता प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।

iv. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम के तहत, मेडिकल कॉलेजों के दूसरे/तीसरे वर्ष के पीजी छात्रों को जिला अस्पतालों में तैनात किया जाता है।

भारत सरकार, एनएचएम के तहत, राजस्थान के चुरू संसदीय क्षेत्र सहित देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों अर्थात जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), विस्तारित पीएमएसएमए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नवजात स्थिरीकरण इकाइयों (एनबीएसयू) और बाल चिकित्सा वार्डों की स्थापना को कार्यान्वित कर रही है।

*****